(d) to (f). Actual cost of the flat will be worked out only after completion of the work.

Maintenance of Government Residential Accommodation in Delhi

3154. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government owned residential accommodations in Delhi are not maintained properly by the three wings of the Central Public Works Department ;

(b) if so, the steps Government propose to take to ensure their proper maintenance ;

(c) the amount of rent received by Government from the residential accommodations and the amount spent on their maintenance ;

(d) whether ceiling fans provided in the residential accommodations have not been serviced/oiled and consequently they either do not work properly or give disturbing sound ; and

(e) if so, the steps Government propose to take to ensure timely servicing/oiling of the fans and also the painting of fans and electrical fittings once in two years ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) and (b). The Government owned residential accommodation in Delhi is being maintained properly as per the maintenance norms and funds limitations.

(c) An amount of Rs. 600.28 lakhs was recoverable during the year 1983-84 on account of rent etc. for residential Government accommodation. This amount does not include the amount recoverable on account of rent etc. in respect of residential Government accommodation placed at the disposal of various Departments of Central/State Governments and other organisation.

An amount of Rs. 893.23 lakhs has been spent on maintenancei (Civil/Ele./Horti.) during 1983-84.

(d) and (e). The ceiling fans provided in the residential accommodation are periodically serviced and oiled to keep them in working condition. Painting of fans and electrical fittings is also normally carried out once in two years.

Setting up of Industries for Processing Marine Fish in Sunderban Region

3155. SHRI NIRMAL SINHA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to setup industries at Nawkhane/Kakdwip/Mathurapur/Patharpratima in Sunderban region for processing marine fishes for trade and manufacture of poultry food from the non-edible small fishes and prawns and other abundantly available and wasted fishes ; and

(b) if so, the details of the scheme and when it will be implemented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान का बन्द किया जाना

3157. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राजस्थान में उदयपुर स्थित सुखाड़िया विश्वविद्यालय को दी जाने वाली अनुदान सहायता बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और क्या इस सहायता के बन्द किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान में कृषि अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इस सहा-

यता को पुन: आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । केवल सहायता के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है, जिस रूप में कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाती है । उसकी जगह उस तरह सहायता दी जाएगी जैसे सामान्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों को दी जाती है ।

(ख) सहायता के स्वरूप में इसलिए परिवर्तन किया गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार इस विश्वविद्यालय को एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय में बदलने के लिए सहमत नहीं हुई । सहायता का स्वरूप बदलने से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विश्वविद्यालय को दी जाने वाली राशि में भारी कमी आयेगी । इस प्रकार की कमी से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं पड़ेगा, यह राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की पर्याप्तता पर निर्भर करेगा ।

(ग) सहायता के स्वरूप को तभी बदला जा सकता है, यदि राज्य सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिये अपनाये गये आदर्श अधिनियम के अनुसार इस विश्वविद्यालय को एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में गठित करेगी और चलायेगी ।

Review of Policy Regarding Allotment of Government Accommodation to House Owning Employees

3158. SWAMI INDERVESH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government's present policy to provide accommodation to Central Government employees is inconsistent as those who are in dire need of accommodation are left out whereas those who are having their own houses in Delhi, get accommodation which results in sub-letting of the accommodation by the later category ;

(b) if so, whether Government propose to change the present policy of allotment ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF): (a) There is no inconsistency with regard to allotment of general pool accommodation to Central Government employees who own houses in Delhi. The allotment Rules provide for imposition of penalties in cases where charge of subletting of Government accommodation is proved.

(b) No, Sir.

(c) Central Government employees who are having their own houses have been made eligible for general pool accommodation on the basis of the recommendations of the National Council (JCM) which were accepted by the Government.

तिलहन बैंकों की स्थापना

3159. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तिलहन बैंकों को स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन बैंकों को स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) तिलहनों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड ने 20-7-84 को हुई अपनी बैठक में क्षेत्रीय तिलहन बैंक स्थापित करने के एक प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी । प्रस्ताव के ब्यौरे बोर्ड द्वारा अभी तैयार किए जाने हैं ।

(ग) तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए